राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4489/2012

डॉ. अरुणा सिंघवी

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री मानवेन्द्र सिंह के साथ सुश्री सौम्या चौधरी
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री गौरव रांका सुश्री वंदना भंसाली, एजीसी के लिए (प्रतिवादी संख्या-1 और 4 के लिए)

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>22/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 12.05.2011 के आदेश (अनुलग्नक 1) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उसे ज्ञापन और आरोप-पत्र दिया गया था और उसके बाद दिनांक 24.01.2012 के आदेश (अनुलग्नक 4) से, जिसके तहत एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादियों के साथ एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रही है, को 1958 के नियम 16 के तहत दिनांक 12.05.2011 को आरोप-पत्र (अनुलग्नक) जारी किया गया था।

2.1 याचिकाकर्ता पर लगभग 10 साल पहले 14 अक्टूबर, 2001 को हुई एक घटना के लिए आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने श्री कमल

सिंह चौधरी से सिरेमिक टूथ कैपिंग के लिए 1,000 रुपये स्वीकार किए थे, जो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है।

2.2. आरोप-पत्र की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्रेरित शिकायत से संबंधित बताई गई है। इसके अनुसरण में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जाल बिछाया और एसीबी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि, जांच के बाद, एसीबी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला वापस ले लिया क्योंकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को प्रचलित बाजार दर के बारे में स्पष्ट रूप से सलाह दी थी क्योंकि सरकारी अस्पताल में सिरेमिक कैपिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

2.3. आरोप पत्र के प्रति अपने विस्तृत उत्तर में याचिकाकर्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता, जो डी. फार्मा की छात्रा है, ने उससे मदद मांगी थी। उसने स्पष्ट किया कि उसने उसे सिरेमिक कैपिंग की आवश्यकता के बारे में बताया था, जो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, और उसे कहीं और उपचार लेने की सलाह दी थी। इसके बावजूद, लगातार अनुरोधों और मदद करने के एकमात्र इरादे से, उसने कैपिंग की व्यवस्था की और 1,000 रुपये जो चार्ज किए गए, वास्तव में बाजार मूल्य थे, न कि उसकी फीस।

2.4. इसके बावजूद, प्रतिवादियों ने 24.01.2012 को एक आदेश पारित किया, जिसके तहत एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. उत्तर में दिए गए उपरोक्त कथन के जवाब में बचाव पक्ष ने कहा है कि अनुशासनात्मक अधिकारी को याचिकाकर्ता के कथित आचरण के बारे में 04.05.2010 को ही पता चला। उसके बाद उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। इसलिए तुरंत आरोप पत्र जारी किया गया। ऐसी स्थिति में, मामला असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है, और इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. मैंने प्रतिस्पर्धी तर्क सुने हैं और केस फाइल का भी अवलोकन किया है।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि आक्षेपित आरोप पत्र केवल देरी और कमियों के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

6. यह माना जाता है कि जिस कथित घटना पर आरोप-पत्र आधारित है, वह 14.10.2001 को हुई थी। आरोप-पत्र 12.05.2011 को जारी किया गया था। कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी देरी आरोपों को गलत साबित करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय बीतने के साथ-साथ मानवीय स्मृति धुंधली हो जाती है और यहां तक कि अपराधी जिस सबूत पर भरोसा कर सकता था, वह भी अब उपलब्ध नहीं हो सकता है और इस तरह याचिकाकर्ता का खुद का बचाव करने का मूल्यवान अधिकार खतरे में पड़ जाता है।

7. अब मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए, देरी के बावजूद, यह पता चलता है कि इसी आरोप के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भी जांच की थी, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा 1000 रुपये का परामर्श शुल्क मांगने के आरोपों के संबंध में कोई तथ्य नहीं मिला, इसलिए उसके खिलाफ एसीबी का मामला समाप्त कर दिया गया।

8. इसके मद्देनजर, आरोपों और तथ्यों के एक ही सेट पर इतनी देरी से विभागीय कार्यवाही शुरू करना, अन्यथा भी गुण-दोष की जांच के दायरे में नहीं आता है।

9. इस आधार पर, तत्काल रिट याचिका को अनुमति दी जाती है, देरी और कमियों के आधार पर और साथ ही साथ अन्य आधारों पर भी, आक्षेपित आरोप-पत्र को संधारणीय नहीं माना जाता है और उसे रद्द किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 12.05.2011 (अनुलग्नक 1) और 24.01.2012 (अनुलग्नक 4) के आक्षेपित आदेशों को भी आने वाले परिणामों के साथ रद्द किया जाता है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।